Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

नवंबर (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तराखंड **3**

- 300वाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी वंदना कटारिया 3
- बदरीनाथ और गौरीकुंड राजमार्ग को जोड़ने वाली 910 मीटर लंबी सुरंग आरपार 4
- अहमदाबाद में 20 हज़ार करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर करार 4
- प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में केदारनाथ धाम शिखर पर 6
- प्रदेश में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के पाँच प्रस्तावों को मिली मंज़ूरी 7
- मुंबई रोड शो में 30,200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर करार 7
- राष्ट्रीय खेल 2023 : उत्तराखंड की झोली में अब तक 17 पदक 8
- उत्तराखंड करेगा असम के साथ सेब का व्यापार 9
- 24 नवंबर से टिहरी झील में होगा अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल 10
- उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग पर मिलेंगे तीन-तीन करोड़ रुपए 11
- आयुष विभाग ने किये चार हज़ार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर करार 13
- यूपीसीएल को सस्ती बिजली देगा एसजेवीएन 13
- उत्तराखंड स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने की कई घोषणाएँ 15
- प्रदेश की पहली योग नीति का प्रस्ताव तैयार 15
- प्रदेश में पहली बार छह खिलाड़ियों को मिलेगा हिमालय पुत्र पुरस्कार 16
- प्रदेश के सभी 119 राजकीय महाविद्यालयों में स्थापित किये जाएंगे देवभूमि उद्यमिता केंद्र 17
- रुद्रपुर में बनेगी राज्य की पहली साइबर सिटी 17
- राज्य सचिवालय में मिलेट बेकरी आउटलेट का शुभारंभ 18
- चारधाम यात्रा 2023: 56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किये दर्शन 19
- झीलों की नगरी नैनीताल का 182वां जन्मदिवस 20
- एमबीबीएस हिंदी पाठ्यक्रम लागू करने के लिये केंद्रीय प्रकोष्ठ और कोर कमेटी गठित 20
- उत्तराखंड में रुद्रपुर में हुआ पहला क्षेत्रीय निवेशक सम्मेलन 21
- सिंगल विंडो से 18 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश को मंज़ूरी, 26 हज़ार को मिलेगा रोज़गार 22
- मुख्यमंत्री ने किया छठवें आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन का शुभारंभ 23
- देश का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन बना सिलक्यारा 25
- महिला होमगार्डों को मिलेगा मातृत्व अवकाश 27

नोट :

उत्तराखंड

300वाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी वंदना कटारिया

चर्चा में क्यों ?

31 अक्टूबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के रोशनाबाद की रहने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड खिलाड़ी वंदना कटारिया ने झारखंड के राँची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में जारी झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी-2023 में 300वाँ अंतर्राष्ट्रीय कैप अर्जित करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है।

प्रमुख बिंदु

- वंदना कटारिया ने मौजूदा महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में जापान के खिलाफ भारत के मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही वंदना 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई।
- भारत मौजूदा महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में अब तक अजेय रहा है। उसने थाईलैंड के खिलाफ अपना पहला गेम 7-1 से जीता, दूसरे मैच में मलेशिया के खिलाफ 5-0 से जीत हासिल की और फिर रोमांचक मुकाबले में चीन को 2-1 से हराया।
- विदित है कि वंदना कटारिया तब सुर्खियों में आई, जब वह जर्मनी के मोनचेंग्लादबाक में जूनियर महिला विश्व कप में भारतीय टीम के लिये शीर्ष स्कोरर रही और टीम को काँस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
- वंदना ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत के चौथे स्थान पर रहने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह ओलंपिक खेलों में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी भी है।
- वंदना को 2022 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अनुभवी फॉरवर्ड खिलाड़ी वंदना 2016 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी और 2017 में महिला एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम की सदस्य थी।

नोट :

बदरीनाथ और गौरीकुंड राजमार्ग को जोड़ने वाली 910 मीटर लंबी सुरंग आरपार

चर्चा में क्यों ?

30 अक्तूबर, 2023 को रुद्रप्रयाग ज़िला मुख्यालय में ऋषिकेश-बदरीनाथ व रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने के लिये 910 मीटर लंबी सुरंग को आरपार कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- भारत सरकार की 'ऑलवेदर रोड परियोजना'के अंतर्गत दूसरे चरण में रुद्रप्रयाग में बदरीनाथ और गौरीकुंड राजमार्ग को आपस में जोड़ने के लिये सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। दिसंबर 2022 में भूमि पूजन के साथ सुरंग निर्माण की कार्रवाई शुरू की गई। जबकि इस वर्ष मार्च में कार्यदायी संस्था भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बेलणी और जगतोली से सुरंग के लिये खोदाई शुरू की।
- कार्यदायी कंपनी को दिसंबर तक इस सुरंग को आरपार करने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन कंपनी ने सात माह में ही 150 मज़दूरों के साथ ही मशीनों की मदद से सुरंग को आरपार कर दिया। कंपनी के आला अधिकारियों की मौजूदगी में सुरंग को बेलणी से जगतोली तक 910 मीटर आरपार किया गया।
- परियोजना के तहत सुरंग के साथ ही अलकनंदा नदी पर 200 मीटर लंबा मोटर पुल भी प्रस्तावित है, जिसके एबेडमेंट के लिये खोदाई जोरों पर चल रहा है। एनएच के अधिकारियों के अनुसार परियोजना का कार्य जून 2025 तक पूरा कर दिया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि बीआरओ ने वर्ष 2008-09 में ज़िला मुख्यालय में सुरंग निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजा था। वर्ष 2016 में भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद तीन चरणों में बीआरओ के अधिकारियों की मौजूदगी में सुरंग निर्माण के लिये सर्वेक्षण किया गया।
- सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2019 में भारत सरकार ने सुरंग निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए इसे ऑलवेदर रोड परियोजना के दूसरे चरण में शामिल किया। साथ ही सुरंग और अलकनंदा नदी पर पुल निर्माण के लिये 200 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी।

अहमदाबाद में 20 हज़ार करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर करार

चर्चा में क्यों ?

1 नवंबर, 2023 को वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिये अहमदाबाद में हुए रोड शो में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में 50 से अधिक उद्योग समूह के साथ 20 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू किये गए।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- अहमदाबाद रोड शो में सीएम धामी और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उद्योग समूहों के साथ बैठक कर राज्य में उद्योग लगाने के लिये प्रोत्साहित किया। इसके बाद शीतल ग्रुप कंपनी, रैंकर्स हॉस्पिटल, जिवाया वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, एस्ट्रल पाइप्स, वारमोरा टाइल्स, गुजरात अंबुजा, एमकेसी इंसा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अमूल के साथ निवेश पर एमओयू किया।
- इसके अलावा कमोडिटी ट्रेडिंग, एडी मेहता लॉजिस्टिक्स, फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ कंपनीज, पारेख वेंचर्स एलएलपी, वी मिलक इंटरप्राइजेज, आर्य ओशियन लॉजिस्टिक्स पार्क, हिन्दुस्तान ऑयल इंडस्ट्रीज, सुपैक इंडस्ट्रीज, श्रीजी ग्रुप, एनबी ग्रुप, शांताकारम निगम, अपोलो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, पंचकर्म होटल और रिसॉर्ट्स (ट्राइडेंट), साबरमती विश्वविद्यालय, लीला होटल और रिसॉर्ट्स, हॉप्स हेल्थकेयर, प्राइम फ्रेश, दत्त मोटर्स, नेक्सस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ निवेश प्रस्ताव पर करार हुआ।
- उल्लेखनीय है कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिये अब तक हुए छह रोड शो (लंदन, दुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बंगलुरू और अहमदाबाद) में 89300 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू हो चुका है।

पंजाब-हरियाणा कोर्ट की जस्टिस रितु बाहरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश

चर्चा में क्यों ?

2 नवंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की न्यायाधीश रितु बाहरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। जस्टिस बाहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट में पूर्व चीफ जस्टिस विपिन सांघी की जगह लेंगी।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी 26 अक्तूबर को सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके बाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं।
- जस्टिस रितु बाहरी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने 14 अक्तूबर, 2023 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का दायित्व संभाला था। वर्तमान में वह पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की दूसरी वरिष्ठतम जज हैं।
- जस्टिस रितु बाहरी के पिता जस्टिस अमृत लाल बाहरी भी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जज रह चुके हैं। जस्टिस रितु बाहरी ने 1986 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में वकालत शुरू की और इसके बाद हरियाणा एडवोकेट जनरल कार्यालय में सेवाएँ दीं। 16 अगस्त, 2010 को उन्हें पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था।

नोट :

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में केदारनाथ धाम शिखर पर

चर्चा में क्यों ?

4 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार नई दिल्ली में शहरी एवं आवास मंत्रालय और राष्ट्रीय नगरीय कार्य संस्थान की ओर से प्लास्टिक और ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिये आयोजित अर्बन लार्नाथोन में सभी राज्यों के शहरी निकायों में उत्तराखंड का केदारनाथ धाम प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में देशभर में शिखर पर रहा।

प्रमुख बिंदु

- देशभर में उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में प्लास्टिक कचरा संग्रहण के लिये लागू डिजिटल डिपोजिट रिफंड सिस्टम को पहला स्थान मिला है, जबकि बैणी सेना स्वयं सहायता समूह हल्द्वानी ठोस कूड़ा प्रबंधन में दूसरे स्थान पर रहा।
- नगर निगम हल्द्वानी में बैणी सेना स्वयं सहायता समूह 57 वार्डों में घर-घर कूड़ा संग्रहण कर रहा है। इसके साथ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकने के लिये लोगों को जागरूक कर रहा है। 70 प्रतिशत परिवारों और दुकानों से यूज़र चार्ज लेकर समूह प्रतिमाह 35 लाख रुपए की आय प्राप्त कर रहा है।
- कार्यक्रम में शहरी एवं आवास मंत्रालय ने उत्तराखंड को अर्बन लार्नाथोन-2023 के विजेता और उपविजेता का पुरस्कार दिया। नगर निगम हल्द्वानी के मेयर जोगेंद्र रौतेला और शहरी विकास विभाग के सहायक निदेशक विनोद कुमार ने पुरस्कार प्राप्त किया।
- विदित है कि पिछली चारधाम यात्रा में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और शहरी विकास विभाग ने केदारनाथ धाम में प्लास्टिक कूड़ा संग्रहण के लिये डिजिटल डिपोजिट रिफंड सिस्टम को लागू किया था।
- 7 जनवरी, 2023 को केंद्र सरकार ने इस सिस्टम को राष्ट्रीय डिजिटल पुरस्कार से सम्मानित किया। इस प्रबंधन के तहत ऊखीमठ विकासखंड को प्लास्टिक रेगुलेटेड ज़ोन घोषित किया गया।
- इसके अलावा प्लास्टिक पानी की बोतल पर क्यूआर लगाए गए। क्यूआर कोड के आधार पर विक्रेता ग्राहक से अतिरिक्त धनराशि लेता था। खरीदने वाला व्यक्ति जब खाली बोतल को निर्धारित दुकानों पर वापस लौटाता है तो उसे अतिरिक्त राशि लौटाई जाती है। केदारनाथ धाम में 15 डिजिटल डिपोजिट रिफंड सिस्टम केंद्र बनाए गए।

नोट :

प्रदेश में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के पाँच प्रस्तावों को मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

3 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के ऊर्जा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय समिति ने सौर ऊर्जा प्रस्ताव की समीक्षा कर 5.26 मेगावाट के पाँच सौर प्रोजेक्ट लगाने के प्रस्तावों को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- इसमें ईविंसिया रेन्युवल प्राइवेट लिमिटेड, सहारा साय प्राइवेट लिमिटेड, टेक्नोक्स इंजीनियरिंग एंड सर्विस, सहारा साय, काशी विश्वनाथ स्टील टैक्सटाइल्स मिल लिमिटेड कुल 5.26 मेगावाट (5265 किलोवाट) के सोलर प्रोजेक्ट लगाएंगी। इसमें 24 करोड़ का निवेश किया जाएगा।
- विदित है कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने सौर नीति के तहत जुलाई 2023 में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने के लिये आवेदन मांगे थे, जिसमें 20 मेगावाट क्षमता के सात प्रोजेक्ट के प्रस्ताव मिले।
- ऊर्जा सचिव ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पीएम के संकल्प पर कार्बन उत्सर्जन कम करने को राज्य सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है।
- ज्ञातव्य है कि प्रदेश में 13 अप्रैल, 2023 को नई सौर ऊर्जा नीति लागू की गई। प्रदेश में मुख्यमंत्री सोलर स्वरोज़गार योजना चलाई गई है। इसके अलावा उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के घरेलू उपभोक्ताओं के लिये रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने हेतु प्रदेश सरकार अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है।

मुंबई रोड शो में 30,200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर करार

चर्चा में क्यों ?

6 नवंबर, 2023 को उत्तराखंड में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुए रोड शो में 30,200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर करार हुए।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में इमेजिका कंपनी से थीम पार्क एवं रिजॉर्ट में, एसीएमई कंपनी से सौर सेल विनिर्माण में, सीटीआरएल कंपनी से डाटा सेंटर में, लॉसंग अमेरिका से आईटी में, पर्फेटी कंपनी, क्रोमा एटोर कंपनी और क्लीन मैक्स एनवाइरो कंपनी से नवीकरणीय ऊर्जा में, साइनस कंपनी से हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश के लिये करार हुआ है।
- इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स, गोदरेज केमिकल्स, एस्टार भोजन, वी अर्जुन लॉजिस्टिक्स पार्क के साथ भी निवेश पर बातचीत हुई।
- निवेशक सम्मेलन के लिये उत्तराखंड प्रदेश सरकार अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाँच और देश में पाँच रोड शो कर चुकी है। इनमें लंदन, बर्मिंघम, अबुधाबी, दिल्ली, चेन्नई, बंगलूरू, अहमदाबाद और मुंबई में रोड शो कर निवेशकों को राज्य में निवेश के लिये प्रोत्साहित किया गया। साथ ही निवेश प्रस्तावों पर एमओयू किया गया।
- विदित हो कि प्रदेश सरकार ने निवेशक सम्मेलन के लिये 2.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा है। आठ व नौ दिसंबर को देहरादून के एफआरआई में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिये रोड शो में अब तक 1,24,200 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हुए हैं।
- गौरतलब है कि प्रदेश में 2018 में हुए पहले निवेशक सम्मेलन में 1.24 लाख करोड़ रुपए के 600 से अधिक प्रस्तावों पर एमओयू हस्ताक्षर हुए थे। लेकिन वर्तमान तक लगभग 30 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश ही धरातल पर उतर पाया है। इस बार अब तक 1,24,200 करोड़ रुपए के करार हो चुके हैं।

राष्ट्रीय खेल 2023 : उत्तराखंड की झोली में अब तक 17 पदक

चर्चा में क्यों ?

6 नवंबर, 2023 को गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में दो रजत और एक कांस्य पदक जीता। इससे उत्तराखंड के पदकों की कुल संख्या 17 हो गई है।

प्रमुख बिंदु

नोट :

- उत्तराखंड के स्नेहा चौहान ने जूडो 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। आर्चरी में डोईवाला देहरादून के कार्तिक राणा ने रजत पदक और जूडो के 78 किलोग्राम वर्ग में उत्तरकाशी की स्नेहा तड़ियाल ने कांस्य पदक जीता।
- 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड पदक तालिका में तीन स्वर्ण और तीन रजत पदक सहित 17 पदक लेकर 23वें स्थान पर है।
- वहीं उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश को अब तक केवल छह पदक मिले हैं, जिसमें दो स्वर्ण, एक रजत और तीन कांस्य पदक हैं। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में 27वें नंबर पर है।

उत्तराखंड करेगा असम के साथ सेब का व्यापार

चर्चा में क्यों ?

5 नवंबर, 2023 को उत्तराखंड के कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तरकाशी ज़िले के हर्षिल में उत्पादित सेब का व्यापार असम की मंडियों में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने गुवाहाटी दौरे पर उत्तराखंड के सेब को असम तक पहुंच बढ़ाने के लिये मंडी विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ये बात कही।
- उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी के हर्षिल का सेब कोलकाता तक पहुँचता है। इसे असम की मंडियों में पहुँचाया जा सकता है। यदि असम उत्तराखंड के साथ सेब का व्यापार करता है, तो इसके लिये प्रदेश सरकार सहयोग करने के लिये तैयार है।
- कृषि मंत्री गणेश जोशी ने असम राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज बरुआ और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तेज प्रसाद भुसाल से असम की फल-सब्जी मंडियों की कार्यप्रणाली और कृषि के क्षेत्र में उर्वरक क्षमताओं, मार्केटिंग, उत्पादन, फसल कटाई के उपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन की जानकारी ली।
- कृषि मंत्री को असम के अधिकारियों ने बताया कि असम कृषि विपणन बोर्ड में 700 कर्मचारी और 42 बोर्ड के सदस्य हैं। असम के गोलपाड़ा ज़िले के ड्रोंगगिरी क्षेत्र केले का बहुत बड़ा उत्पादक है, जहाँ से देश के कई राज्यों के लिये केले भेजे जाते हैं।

नोट :

24 नवंबर से टिहरी झील में होगा अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल

चर्चा में क्यों ?

5 नवंबर, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के माध्यम से टिहरी झील में 24 से 28 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश दुनिया के पायलट हवा में करतब दिखाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के पर्यटन मानचित्र में टिहरी झील सबसे तेजी से उभरता हुआ नया स्थल है, जहाँ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है।
- एक्रो फेस्टिवल में रोमांचकारी प्रतिस्पर्धा करने के लिये 35 अंतर्राष्ट्रीय और 100 भारतीय पायलट भाग लेंगे।
- इस आयोजन में एक्रो फ्लाइंग, सिंक्रो फ्लाइंग, विंग सूट फ्लाइंग, डी-बैगिंग जैसे साहसिक प्रतियोगिताएं होंगी। आयोजन के दौरान यूफोरिया, पांडवास जैसे नामी बैंड भी शाम के समय अपनी प्रस्तुति देंगे।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड को वैश्विक पहचान दिलाने और साहसिक पर्यटन में उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिये राज्य सरकार काम कर रही है। इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल नए आयाम स्थापित करेगा।

नोट :

उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग पर मिलेंगे तीन-तीन करोड़ रुपए

चर्चा में क्यों ?

7 नवंबर, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता-निर्देशकों और कलाकारों को प्रस्ताव देते हुए एलान किया है कि राज्य में हिंदी फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग पर उत्तराखंड सरकार अब तीन-तीन करोड़ रुपए की अनुदान देगी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता-निर्देशकों और कलाकारों से मुलाकात करके उत्तराखंड में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयासों पर चर्चा की और मुंबई के लोगों को उत्तराखंड में शूटिंग के लिये आमंत्रित किया।
- प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम धामी ने बताया कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड में शूटिंग को बढ़ावा देने के लिये अब फिल्मों के अलावा वेब सीरीज की शूटिंग पर भी अनुदान देने का फैसला किया है।
- उन्होंने बताया कि फिल्मों को मिलने वाली राशि को दोगुना कर दिया है। अब राज्य में हिंदी फिल्मों की शूटिंग करने पर तीन करोड़ रुपए, क्षेत्रीय फिल्मों की शूटिंग पर दो करोड़ रुपए और वेब सीरीज की शूटिंग पर तीन करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी।
- गौरतलब है कि उत्तराखंड में शूटिंग के लिये अब तक हिंदी फिल्मों की शूटिंग पर 1.50 करोड़ रुपए, क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के लिये 25 लाख रुपए और दूसरे प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषा फिल्मों की शूटिंग पर 15 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान इस बात की भी घोषणा की कि अगर कोई उत्तराखंड में शूटिंग के लिये स्टूडियो खोलना चाहता है तो उसे 50 लाख रुपए, थियेटर खोलने के लिये 25 लाख रुपए और पोस्ट प्रोडक्शन स्टुडियो के लिये 25 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
- शूटिंग के लिये सिंगल विंडो सिस्टम व्यवस्था शुरू किये जाने के अलावा उन्होंने ये भी बताया कि शूटिंग के लिये आने वाली प्रोडक्शन टीम को होटल में ठहरने के लिये 50 प्रतिशत डिस्काउंट दिया जाएगा और शूटिंग के दौरान सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखा जाएगा।

नोट :

नोट :

आयुष विभाग ने किये चार हज़ार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर करार

चर्चा में क्यों ?

7 नवंबर, 2023 को उत्तराखंड आयुष विभाग के सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिये आयुष विभाग ने अब तक चार हज़ार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि उत्तराखंड में आयुष और वेलनेस क्षेत्र में नए निवेश से आने वाले समय में छह हज़ार लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे।
- सरकार ने आयुष व वेलनेस क्षेत्र में पाँच हज़ार करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। आयुष विभाग ने लक्ष्य के सापेक्ष चार हज़ार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू किया है।
- इसमें पतंजलि के साथ एक हज़ार करोड़ रुपए के निवेश पर करार हुआ है। पतंजलि प्रदेश में वेलनेस, योग और औषधीय पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने में निवेश करेगा।
- इसके अलावा कुमार ग्रुप के साथ वेलनेस व योग में 1700 करोड़ रुपए के निवेश पर एमओयू किया गया है।
- सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन से पहले 800 करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर उतारा जाएगा। आयुष नीति में वेलनेस, आयुष क्षेत्र में निवेश करने पर पाँच प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है।

यूपीसीएल को सस्ती बिजली देगा एसजेवीएन

चर्चा में क्यों ?

8 नवंबर, 2023 को एसजेवीएन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने बताया कि उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) को एसजेवीएन अपने सौर ऊर्जा संयंत्र से 200 मेगावाट बिजली देगा। इसके लिये यूपीसीएल का आशय पत्र प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- नंदलाल शर्मा ने बताया कि यूपीसीएल-एसजेवीएन की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर परियोजना से 2.57 रुपए प्रति यूनिट के टैरिफ पर बिजली खरीदने का इच्छुक है।
- परियोजना से सौर ऊर्जा का आवंटन निकट भविष्य में एसजीईएल और यूपीसीएल के बीच हस्ताक्षरित होने वाले विद्युत खरीद करार के अनुसार होगा।

नोट :

- विदित हो कि तीन जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीकानेर सौर परियोजना की आधारशिला रखी थी। यह परियोजना जून 2024 तक कमीशन होगी।
- यह सौर परियोजना सीपीएसयू योजना के अंतर्गत राजस्थान में एसजेवीएन की पूर्ण स्वामित्व वाली अधीनस्थ कंपनी एसजीईएल के माध्यम से विकसित की जा रही है।
- बीकानेर सौर परियोजना से 25 वर्षों में संचयी रूप से लगभग 56,838 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न होने की संभावना है, जबकि कार्बन उत्सर्जन में 27,85,077 टन की कमी आएगी।

नोट :

उत्तराखंड स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने की कई घोषणाएँ

चर्चा में क्यों ?

9 नवंबर, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित पुलिस लाइन में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश में नई नीतियों को लागू करने संबंधी कई घोषणाएँ की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला नीति तैयार हो गई है। जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।
- उन्होंने जरूरतमंद परिवारों के लिये 'मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना' की भी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार जरूरतमंद परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिये यह योजना शुरू करेगी। ज़िला स्तर पर इस तरह के आयोजन किये जाएंगे। यह सारी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी।
- मुख्यमंत्री ने बाल श्रम उन्मूलन के लिये सभी विभागों के समन्वय के साथ एक विशिष्ट कार्ययोजना बनाने का एलान किया। देवभूमि के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिये सरकार इस कार्ययोजना पर शीघ्र काम करेगी।
- वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने के लिये नशा मुक्त ग्राम और नशा मुक्त शहर योजना भी शुरू करेंगे। इसके तहत चिह्नित क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन देंगे।
- इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य की चार विभूतियों माधुरी बड़थ्वाल, बसंती बिष्ट, सच्चिदानंद भारतीय तथा राजेंद्र सिंह बिष्ट को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा के लिये 'उत्तराखंड गौरव सम्मान' से सम्मानित किया।

प्रदेश की पहली योग नीति का प्रस्ताव तैयार

चर्चा में क्यों ?

9 नवंबर, 2023 को उत्तराखंड के आयुष सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि प्रदेश की पहली योग नीति का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जल्द ही सरकार इस नीति को मंज़ूर दे सकती है।

प्रमुख बिंदु

- इस नीति के तहत प्रदेश में योग, आध्यात्मिक और नेचुरोपैथी सेंटर स्थापित करने के लिये सरकार वित्तीय प्रोत्साहन देगी।

नोट :

- पर्यटन नीति के अनुसार बी और सी श्रेणी में चयनित पर्वतीय क्षेत्रों में योग और आध्यात्मिक सुविधाओं में निवेश करने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा आयुष नीति के तहत पांच प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।
- इस नीति को लागू करने के लिये आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग नोडल होगा। निवेश प्रस्ताव को सिंगल विंडो सिस्टम से मंज़ूरी दी जाएगी।
- प्रदेश सरकार उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय योग हब बनाने के लिये प्रयासरत है। इसलिये हर साल पर्यटन विभाग की ओर से ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया जाता है।
- विदित हो कि अभी तक प्रदेश में योग की बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिये कोई नीति नहीं थी।

प्रदेश में पहली बार छह खिलाड़ियों को मिलेगा हिमालय पुत्र पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

12 नवंबर, 2023 को उत्तराखंड के खेल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में पहली बार छह खिलाड़ियों को हिमालय पुत्र पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।। इसमें एक दिव्यांग, दो टीम एवं तीन व्यक्तिगत स्पर्धा के खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार के लिये चयन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले इन खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और खेल प्रशिक्षक को देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से हर साल सम्मानित किया जाता है, लेकिन खिलाड़ियों को हिमालय पुत्र पुरस्कार पहली बार मिलने जा रहा है।
- खेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, खेल निदेशालय को 16 अक्तूबर तक कई पुरस्कारों के लिये आवेदन मिल चुके हैं। आवेदनों की जांच के बाद इसके लिये गठित कमेटी की बैठक होगी।
- कमेटी के माध्यम से चयनित खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षक का नाम शासन को भेजा जाएगा। शासन की हाईपावर कमेटी और खेल मंत्री के अनुमोदन के बाद पुरस्कारों के लिये नाम घोषित किये जाएंगे।
- इन पुरस्कारों के लिये नाम भी होंगे घोषित : प्रदेश के एक खिलाड़ी को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, एक को लाइफ टाइम अचीवमेंट और एक खेल प्रशिक्षक को देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलेगा।

नोट :

प्रदेश के सभी 119 राजकीय महाविद्यालयों में स्थापित किये जाएंगे देवभूमि उद्यमिता केंद्र

चर्चा में क्यों ?

11 नवंबर, 2023 को देवभूमि उद्यमिता योजना के नोडल अधिकारी एवं सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा डॉ. दीपक कुमार पांडेय ने बताया कि प्रदेश के सभी 119 राजकीय महाविद्यालयों में देवभूमि उद्यमिता केंद्र स्थापित किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. दीपक कुमार पांडेय ने बताया कि योजना का उद्देश्य राज्य के विश्वविद्यालयों एवं राजकीय संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप नवाचार एवं उद्यम का पारिस्थितिक तंत्र विकसित करना है।
- देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत 90 प्राध्यापकों को उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत छात्रों में उद्यमशील गुणों की पहचान करने के बाद उनका विकास किया जाएगा।
- विदित हो कि राज्य उच्च शिक्षण संस्थाओं के 22 संकाय सदस्यों ने ईडीआईआई, अहमदाबाद में पाँच नवंबर से 10 नवंबर तक प्रशिक्षण लिया है। नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग से सदस्यों ने इसमें प्रतिभाग किया।
- उद्यमिता केंद्रों में निम्नलिखित विषयों पर फोकस किया जाएगा-
  - छात्रों में उद्यमशील गुणों को पहचान करना और उनका विकास करना।
  - स्टार्ट-अप अवसर की पहचान करना।
  - उद्यमिता पर पाठ्यक्रम विकसित करना।
  - स्टार्ट-अप फंडिंग और वेंचर कैपिटल।
  - उत्तराखंड में उद्यमिता के उभरते अवसर और उनके प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाना।
  - एनईपी-2020 के अनुसार कौशल-विकास पाठ्यक्रम कोर्स डिजाइन करना।
  - पुस्तकालय संसाधन और आईटी पर चर्चा।

रुद्रपुर में बनेगी राज्य की पहली साइबर सिटी

चर्चा में क्यों ?

15 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड राज्य सरकार ऊधमसिंह नगर ज़िले के रुद्रपुर के आस-पास राज्य की पहली साइबर सिटी बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। टाटा और इंफोसिस ने निवेश के लिये हामी भरी है।

प्रमुख बिंदु

- आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को अंजाम देने के लिये सरकार आईटी क्षेत्र की नामी कंपनियों से बात कर रही है। टाटा और इंफोसिस जैसी कंपनियों ने इसमें नवेश के लिये हामी भरी है। कंपनियों के सुझाव पर सरकार आईटी व सेवा क्षेत्र की नीतियों में भी बदलाव कर सकती है।
- आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, आईटी सेक्टर में टाटा 5000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकता है। निवेश की राशि परिस्थितियों के अनुरूप और अधिक हो सकती है। इसके अलावा आईटी सेक्टर की अग्रणी कंपनी इंफोसिस इंफोसिस भी उत्तराखंड में बड़ा निवेश कर सकती है।
- सरकार की योजना एक ही स्थान पर सभी आईटी कंपनियों को भूमि उपलब्ध कराने की है। साइबर सिटी के लिये रुद्रपुर में पराग फार्म के पास उपलब्ध भूमि पर आईटी कंपनियों को भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है।
- सरकार की आईटी सेक्टर में 20-30 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश जुटाने का लक्ष्य है। यदि राज्य सरकार अपने लक्ष्य को हासिल कर लेती है, तो साइबर सिटी बनाए जाने की राह आसान हो जाएगी।

नोट :

राज्य सचिवालय में मिलेट बेकरी आउटलेट का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

16 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के मोटे अनाज़ों पर आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने और महिला स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि करने के उद्देश्य से सचिवालय परिसर में मिलेट बेकरी आउटलेट का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि राज्य में ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्थानीय मंडुआ, झंगोरा, ज्वार, चौलाई इत्यादि अनाज़ों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इन उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिये देहरादून के रायपुर ब्लॉक व पौड़ी ज़िले के पौड़ी ब्लॉक में दो मिलेट उत्पादों की बेकरी शुरू की गई है।
- मिलेट बेकरी में मंडुआ व झंगोरा का प्रसंस्करण कर बिस्किट, ब्रेड व पिज्जा बेस व अन्य उत्पाद तैयार किये जा रहे हैं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के अंतर्गत स्थानीय मोटे अनाज़ों के उत्पादन और उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिये प्रदेश में अनेक कार्यक्रम किये जा रहे हैं।

नोट :

- उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक सवा लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 40,270 महिलायें लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं।
- चयनित स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को बेकरी विशेषज्ञ के माध्यम से बेकरी उत्पाद हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे अधिक संख्या में समूहों द्वारा बाज़ार की माँग के अनुरूप उच्च गुणवत्ता तथा पोषण से युक्त बेकरी उत्पाद तैयार कर लोगों को उपलब्ध करा सके।

चारधाम यात्रा 2023: 56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किये दर्शन

चर्चा में क्यों ?

18 नवंबर, 2023 तक चली चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आये 56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर नया रिकॉर्ड बनाया है। यात्रा के इतिहास में चारधाम समेत हेमकुंड साहिब में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड बना है।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि 22 अप्रैल से 18 नवंबर तक चली चारधाम यात्रा के लिये लगभग 75 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया था। इसमें केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब में 56.13 लाख से अधिक ने दर्शन किये।
- यात्रा के इतिहास में पहली बार श्रद्धालुओं का आँकड़ा 55 लाख पार हुआ है। केदारनाथ धाम में सबसे अधिक 19.61 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किये। इसके बाद बदरीनाथ में 18.34 लाख, गंगोत्री में 9.05 लाख, यमुनोत्री में 7.35 लाख और हेमकुंड साहिब में 1.77 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किये।
- वर्ष 2022 में चारधाम व हेमकुंड साहिब यात्रा में 46.29 लाख श्रद्धालु पहुँचे थे। इससे पहले 2021 और 2020 में कोविड काल में चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो पाई है। 2021 में 5.29 लाख और 2020 में मात्र 3.30 लाख तीर्थयात्री पहुँचे थे। वर्ष 2019 में 34.77 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा में आए थे।

नोट :

झीलों की नगरी नैनीताल का 182वां जन्मदिवस

चर्चा में क्यों ?

18 नवंबर, 2023 को उत्तराखंड की पर्यटन नगरी एवं झीलों की नगरी नैनीताल का 182वां जन्मदिवस मनाया गया।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि 18 नवंबर, 1841 को नैनीताल पहुंचे अंग्रेज व्यापारी पी बैरन ने यहाँ की सौंदर्य से प्रभावित होकर इसे दुनिया की नजरों में लाया। अंग्रेज व्यापारी के आगमन की तारीख को ही नैनीताल के जन्मदिन के रूप में याद किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि 1842 में चौथे कुमाऊं कमिश्नर जार्ज थॉमस लुसिंगटन ने आधिकारिक रूप से नैनीताल को यूरोपियन सेटेलमेंट के तहत बसाया था। इसके बाद अंग्रेजों ने इसे छोटी विलायत का दर्जा देते हुए ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया।
- पर्यटन नगरी नैनीताल प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द्र का भी संदेश देती है। नैनीताल के नैनी झील के उत्तरी किनारे पर 51 शक्तिपीठों में से एक मां नयना देवी मंदिर स्थित है। साथ ही यहाँ गुरुद्वारा, एशिया का पहला मेथोडिस्ट चर्च और जामा मस्जिद भी स्थित है।
- अनियंत्रित और अनियोजित विकास के कारण नैनीताल की खूबसूरती और पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बढ़ते कंक्रीट के जंगल पर रोक लगाने, यातायात के दबाव को कम करने, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को जागरूक करने और प्रकृति से छेड़छाड़ पर रोक लगाने के लिये कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है।

एमबीबीएस हिंदी पाठ्यक्रम लागू करने के लिये केंद्रीय प्रकोष्ठ और कोर कमेटी गठित

चर्चा में क्यों ?

22 नवंबर, 2023 को एमबीबीएस की पढ़ाई में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम लागू करने के लिये सरकार ने केंद्रीय प्रकोष्ठ एवं कोर कमेटी गठित कर दी है। एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति कमेटी के अध्यक्ष होंगे। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा नमामि बंसल की ओर से जारी आदेश के अनुसार कमेटी में चिकित्सा शिक्षा निदेशक सह अध्यक्ष होंगे। जबकि सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सदस्य और दून मेडिकल कॉलेज के रेडियोथैरेपी विभागाध्यक्ष प्रो. दौलत सिंह सदस्य सचिव होंगे।

नोट :

- एमबीबीएस में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम लागू करने के लिये मेडिकल कॉलेज स्तर पर उप समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें कॉलेज के प्राचार्य या डीन समिति के अध्यक्ष होंगे। प्राचार्य की ओर से नामित संकाय सदस्य को सचिव, तीन संकाय के विभागाध्यक्ष सदस्य नामित होंगे।
- इसके अलावा हिंदी भाषा पाठ्यक्रम को लेकर कमेटी की सिफारिशों पर अमल करने के लिये एचएनबी चिकित्सा विवि को नोडल एजेंसी नामित किया गया।
- विदित है कि विश्वविद्यालय ने एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी भाषा में करने के लिये पाठ्यक्रम की रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। प्रदेश सरकार शीघ्र ही एमबीबीएस कोर्स में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम लागू करने की तैयारियाँ कर रही है।

उत्तराखंड में रुद्रपुर में हुआ पहला क्षेत्रीय निवेशक सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

22 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में ग्लोबल इंवेस्टर समिट के तहत रुद्रपुर में पहला क्षेत्रीय निवेशक सम्मेलन आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- क्षेत्रीय निवेशक सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि देश-विदेश में कई करोड़ों के करार होने के बाद उत्तराखंड में 12,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव और मिल गया है। राज्य ने कुल डेढ़ लाख करोड़ रुपए निवेश पर करार किया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के विकास-विस्तार और नए उद्योग लगाने के लिये लंदन, दुबई, चेन्नई, बंगलूरू, अहमदाबाद के उद्योगपतियों से संपर्क किया गया है। उत्तराखंड में निवेश के लिये उद्योगपति मुकेश अंबानी से भी वार्ता की गई है। प्रदेश में आईटीसी कंपनी, महिंद्रा, अशोक लेलैंड आदि कंपनियां निवेश करेंगी।
- उन्होंने कहा कि पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये 27 नई पॉलिसी बनाई जा रही हैं। प्रदेश में एडवेंचर-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपति उत्तराखंड के ब्रांड एंबेसडर हैं। उद्योग समूह के लोगों के योगदान से 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार और यूएस नगर में 6000 एकड़ लैंड बैंक उपलब्ध है।

नोट :

सिंगल विंडो से 18 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश को मंज़ूरी, 26 हज़ार को मिलेगा रोज़गार

चर्चा में क्यों ?

26 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नवंबर माह तक लगभग 18 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रस्ताव में सबसे अधिक निवेश देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधम सिंह नगर ज़िले के लिये है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में भी निवेशकों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
- इस निवेश से लगभग 26 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा।
- राज्य में औद्योगिक निवेश प्रस्तावों के लिये विभिन्न विभागों की अनुमति के लिये प्रदेश सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है।
- देहरादून में 8 व 9 दिसंबर, 2023 को होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिये हुए रोड शो में दो लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू हो चुके हैं, जबकि प्रदेश सरकार ने सम्मेलन के लिये 2.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है।

ज़िला	निवेश करोड़ में
अल्मोड़ा	51.32
बागेश्वर	19.09
चंपावत	11.3
चमोली	1.95
देहरादून	1172.09
हरिद्वार	868.6
नैनीताल	602.17
पौड़ी	63
पिथौरागढ़	64.83
रुद्रप्रयाग	99.19
टिहरी	245.72

नोट :

ऊधम सिंह नगर	1064.91
उत्तरकाशी	24.68
राज्यस्तरीय	13313.

मुख्यमंत्री ने किया छठवें आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

28 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्थित क्लेमेंट टाउन स्थित ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय में छठवें आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुभव पर आधारित पुस्तक 'रेजिलिएंट इंडिया' का विमोचन भी किया।
- 1 दिसंबर, 2023 तक होने वाले इस सम्मेलन में 50 से देशों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में 60 से अधिक तकनीकी सत्र आयोजित किये जाएंगे।
- सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यह आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन महत्त्वपूर्ण है। इस संबंध में वैश्विक स्तर पर हो रहे अध्ययनों, शोधों एवं अनुभवों को साझा करना भी समय की जरूरत है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 8 और 9 दिसंबर, 2023 को देहरादून में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश-विदेश के औद्योगिक समूहों, निवेशकों की ओर से राज्य में निवेश को गति देने के लिये प्रतिभाग किया जाएगा। इस सम्मेलन से ठीक पहले आयोजित आपदा प्रबंधन के वैश्विक सम्मेलन से 'सुरक्षित निवेश-सुदृढ़ उत्तराखंड' का संदेश देश-विदेश में जाएगा।
- उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से समेकित विकास लक्ष्यों के साथ-साथ आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन जनित चुनौतियों का बेहतर रूप से सामना करने में सहायता मिलेगी।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में आपदा प्रबंधन के पाठ्यक्रम शामिल किये जाएंगे और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके लिये भूमि की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। इसके अलावा संस्थान को खोलने के लिये केंद्र सरकार की ओर से जो भी अपेक्षा की जाएगी, राज्य सरकार उसे पूरा करेगी।

नोट :

नोट :

देश का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन बना सिलक्यारा

चर्चा में क्यों ?

28 नवंबर, 2023 को उत्तरकाशी ज़िले के सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में भू-धंसाव से फँसे 41 मज़दूरों को 17 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद सफलतापूर्वक बाहर निकल लिया गया। इसके साथ ही ऑपरेशन सिलक्यारा किसी सुरंग या खदान में फँसे मज़दूरों को निकालने वाला देश का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि 12 नवंबर को दीपावाली के दिन उत्तरकाशी ज़िले के सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में भू-धंसाव से 41 मज़दूर अंदर फँस गए थे। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिये विभिन्न एजेंसियाँ जुटी थीं।
- मिशन सिलक्यारा में बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, आरवीएनएल, एसजेवीएनएल, ओएनजीसी, आईटीबीपी, एनएचएआईडीसीएल, टीएचडीसी, उत्तराखंड राज्य शासन, ज़िला प्रशासन, थल सेना, वायुसेना, श्रमिकों की अहम भूमिका रही।
- उल्लेखनीय है कि 17 दिन तक चला ऑपरेशन सिलक्यारा किसी सुरंग या खदान में फँसे मज़दूरों को निकालने वाला देश का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन बन गया है। इससे पहले भी देश में इस तरह के अभियान को अंजाम दिया जा चुका है।
- रानीगंज कोयला खदान अभियान-
  - 13 नवंबर, 1989 को पश्चिम बंगाल के महाबीर कोल्यारी रानीगंज कोयला खदान जलमग्न हो गई थी। इसमें 65 मज़दूर फँस गए थे। इनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिये खनन इंजीनियर जसवंत गिल के नेतृत्व में टीम बनाई गई। दो दिन के ऑपरेशन के बाद आखिरकार सभी मज़दूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
  - उस अभियान में गिल लोगों को बचाने के लिये खुद एक स्टील कैप्सूल के माध्यम से खदान के भीतर गए थे। 1991 में तत्कालीन राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन ने उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा था।
  - उस अभियान में मज़दूरों की संख्या सिलक्यारा से ज्यादा थी, लेकिन उन्हें निकालने में समय कम लगा था। सिलक्यारा में 13वाँ दिन बीतने के बाद मज़दूर बाहर निकाले जा सके।
- कुछ ऐसा ही एक अभियान वर्ष 2006 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र के हल्ढेरी गाँव में हुआ था, जहाँ एक पाँच साल का बच्चा प्रिंस बोरवेल में गिर गया था। करीब 50 घंटे की कड़ी जद्दोजहद के बाद बचाव दलों ने बच्चे को बाहर निकालने में कामयाबी पाई थी। इस अभियान में बराबर के ही अन्य बोरवेल को तीन फीट व्यास के लोहे के पाइप के माध्यम से जोड़कर बच्चे को बाहर निकाला गया था।
- कुछ ऐसे ही अभियान विदेशों में भी हुए हैं-
  - थाई गुफा अभियान: 23 जून, 2018 को थाईलैंड की थाम लुआंग गुफा में गई वाइल्ड बोअर्स फुटबॉल टीम बारिश के कारण हुए जलभराव की वजह से भीतर फँस गई। गुफा में लगातार बढ़ रहे पानी के बीच खिलाड़ियों को खोजना बेहद चुनौतीपूर्ण काम था। करीब दो सप्ताह तक चले अभियान में 90 गोताखोर भी लगाए गए। इस बचाव अभियान में पूर्व थाईलैंड के नेवी सील समन कुनान को जान गवानी पड़ी। यह दुनिया के सबसे जटिल रेस्क्यू अभियान में से एक माना जाता है।
  - चीली खदान अभियान: 5 अगस्त, 2010 को सैन जोस सोने और तांबे की खदान के ढहने से 33 मज़दूर उसमें दब गए थे। ज़मीन के ऊपर से करीब 2000 फीट नीचे फँसे इन मज़दूरों से संपर्क करना ही मुश्किल था। 17 दिन की मेहनत के बाद सतह के नीचे एक लाइफलाइन छेद बनाकर फँसे मज़दूरों को भोजन, पानी, दवा भेजी जा सकी। 69 दिन के बाद 13 अक्तूबर को सभी मज़दूरों को एक-एक करके सुरंग से बाहर निकाला गया।
  - क्यूक्रीक माइनर्स अभियान: 24 जुलाई, 2002 को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के समरसेट काउंटी की क्यूक्रीक माइनिंग इंक खदान में 9 मज़दूर फँस गए। इन्हें केवल 22 इंच चौड़ी आयरन रिंग के सहारे 77 घंटे बाद बाहर निकाला जा सका था।

नोट :

नोट :

महिला होमगार्डों को मिलेगा मातृत्व अवकाश

चर्चा में क्यों ?

28 नवंबर, 2023 को उत्तराखंड राज्य शासन की ओर से अन्य विभागों की तरह ही महिला होमगार्डों को मातृत्व अवकाश दिये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। अब महिला होमगार्डों को भी मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि अब तक प्रदेश में होमगार्डों को मातृत्व अवकाश की सुविधा नहीं थी, लेकिन हाल ही में आईजी केवल खुराना की ओर से पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में तैनात महिला कर्मचारियों की तरह महिला होमगार्डों के लिये भी शासन से मातृत्व अवकाश की सिफारिश की गई थी।
- राज्य शासन ने आईजी केवल खुराना की सिफारिश को गंभीरता से लिया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने महिला होमगार्डों को भी मातृत्व अवकाश प्रदान करने की अनुमति दे दी है।
- प्रदेश में छह हज़ार से अधिक महिला और पुरुष होमगार्ड हैं। आईजी केवल खुराना की ओर से लगातार होमगार्डों को हाईटेक बनाने और पुलिस की तरह ही सुविधा मुहैया कराई जा रही है।
- मातृत्व अवकाश के दौरान महिला होमगार्डों का वेतन नहीं कटेगा। उन्हें मातृत्व अवकाश का पूरा वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा मातृत्व अवकाश के दौरान उच्चाधिकारी महिला होमगार्ड के कुशलक्षेम की भी जानकारी लेंगे।

नोट :